



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जनवरी, 2021 ई0 (पौष 12, 1942 शक सम्वत्) [संख्या-01

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	01-12	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	01-40	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	—	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

## अधिसूचना

09 नवम्बर, 2020 ई0

संख्या 2038/II(2)/2020-06(65)/2016-चूंकि राज्य सरकार जनपद हरिद्वार के तहसील हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले हरिपुर कलां से चण्डी पुल तक गंगा नदी के दोंये तट पर अनुसूची-एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है ;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

## अनुमन्य कार्यों का विवरण

क्र०सं०	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, सिंचाई/जल विद्युत परियोजनाओं के विपथन (Diversion) आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियों, समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी— प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी हरिद्वार एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ-साथ जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

अधिसूचना संख्या 2038/II(02)/2020-06(65)/2016, दिनांक 09 नवम्बर, 2020

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में आने वाले समस्त परिसम्पत्ति का विवरण

जनपद हरिद्वार के तहसील-हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

**प्रतिषिद्ध (Prohibited Area) क्षेत्रों की अनुसूची -01**

क्र० सं०	ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू उपयोग	भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
					भूमि का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम हरिपुर खुर्द	26	1/23म, 1/24 म	0.2360	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	-
		29	1/23 म	0.0390	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		05	1/25म	0.0620	आबादी	वर्ग-9 (NZA)	
		07	1/26म	0.0300	आबादी	वर्ग-9 (NZA)	
		09	1/27म	0.0070	आबादी	वर्ग-9 (NZA)	
		04	1/28म	0.0030	आबादी	वर्ग-15(4) (NZA)	
		23	2म, 3म	0.7750	बांध	वर्ग-15(4) (NZA)	
		22	4, 5	0.6850	गंगाजी	वर्ग-15(1) (NZA)	
		25	1/1म	0.2500	आबादी गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर	
		10	1/1म	1.2600	आबादी, बाग आम गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर	
		03	1/1म	0.2700	आबादी, गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर	
		06	1/1म	0.0600	आबादी,	संक्रमणीय भूमिधर	
			योग हरिपुर खुर्द	3.6770			

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ग्राम लालजीवाला	7	3म	0.0800	नहर	वर्ग-15(4) (NZA)	
		6	4, 6म	0.6970	बन्धा नाला	वर्ग-15(4) (NZA)	
		8	5	0.1740	पथरोड	वर्ग-15(4) (NZA)	
		9	17म, 19म	1.0420	पथरी नाला	वर्ग-15(4) (NZA)	
		4	18म, 20	2.7920	नाला	(NZA)	
		5	21	0.9120	आबादी	(NZA)	
		3	22म	3.8490	गंगाजी	(NZA)	
		1	22म	15.9310	आबादी	(NZA)	
		2	22म	0.6850	गंगाजी	(NZA)	
			योग लालजीवाला	26.162			
			योग प्रतिषिद्ध	29.839			

अधिसूचना संख्या 2038/II(02)/2020-06(65)/2016, दिनांक 09 नवम्बर, 2020.

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में आने वाले समस्त परिसम्पत्ति का विवरण

जनपद हरिद्वार के तहसील--हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

**निबन्धित (Restricted Area) क्षेत्रों की अनुसूची -02**

क्र० सं०	ग्राम का नाम	खाता खतोनी संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप / क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू उपयोग	भूमि की श्रेणी	अन्यविवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम हरिपुर खुर्द	26	1/23म 1/24म	0.2470	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		29	1/23म	0.0200	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		05	1/25म	0.2050	आबादी	वर्ग-9 (NZA)	
		07	1/26म	0.1750	आबादी	वर्ग-9 (NZA)	
		09	1/27म	0.0540	आबादी	वर्ग-9 (NZA)	
		04	1/28म	0.1750	आबादी	वर्ग-9 (NZA)	
		08	1/29म	0.1780	आबादी	वर्ग-9 (NZA)	
		06	1/30	0.6840	आबादी व कृषि	वर्ग-9 (NZA)	
		21	1/22म, 1/31	0.2010	बांध	वर्ग-15(4) (NZA)	
		01	1/32, 1/33	1.2170	आबादी	वर्ग-8 (NZA)	
		15	1/33म	0.0640	आबादी	वर्ग-10क (NZA)	
		16	1/33म	0.0330	आबादी	वर्ग-10क (NZA)	
		23	2म, 3म	0.7830	बांध	वर्ग-15(4) (NZA)	
		25	1/1म	0.2500	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		10	1/1म	0.9050	बाग आम	संक्रमणीय भूमिधर	
		03	1/1म	0.4000	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
		06	1/1म	0.0330	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	
			योग हरिपुर खुर्द	5.6240			

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ग्राम लालजीवाला	7	3म	0.0700	नहर	वर्ग-15(4) (NZA)	
		6	6म	0.0900	बांध नाला	वर्ग-15(4) (NZA)	
		9	17म, 19म	0.1000	पटरी नाला	वर्ग-15(4) (NZA)	
		4	18म	0.2050	नाला	वर्ग-15(1) (NZA)	
		3	22म	0.6000	गंगाजी	वर्ग-15(1) (NZA)	
		1	22म	0.2000	भू-दान समिति गंगाजी	वर्ग-15(1) (NZA)	
			योग लालजीवाला	1.2650			
			योग निर्बन्धित	6.889			
			कुल योग (प्रतिषिद्ध+निर्बन्धित)	36.728			

अधिसूचना संख्या 2038/II(02)/2020-06(65)/2016, दिनांक 09 नवम्बर, 2020

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के तहसील हरिद्वार में गंगा नदी के दांये तट पर हरिपुर खुर्द से चण्डीपुल तक ग्रामवार निर्बन्धित चिह्नित भूमि की अधिसूचना का सारांश

क्र० सं०	ग्राम का नाम	रकबा (हैक्ट० में)	तहसील	चिह्नित भूमि का क्षेत्रफल (हैक्ट० में)
1	हरिपुर खुर्द	9.669	हरिद्वार	5.620
2	लालजीवाला	10.162	हरिद्वार	1.265
	कुल योग :-	19.831		6.885

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,  
सचिव।

**गृह अनुभाग-01****विज्ञप्ति/पदोन्नति**

20 नवम्बर, 2020 ई0

संख्या 758/XX(1)-2020-2(25)2004-मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 310/1996 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश, दिनांक 03.07.2018 के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड संवर्ग के महानिदेशक रैंक के अधिकारियों में से नामों का पैनल तैयार किये जाने के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में दिनांक 12.11.2020 को आहूत बैठक में निम्नानुसार नामों के पैनल की संस्तुति प्रेषित की गयी है :-

S.No.	Name	Date of Birth
1	Shri M.A. Ganapathy (IPS:RR-1986)	01-03-1964
2	Shri Ashok Kumar (IPS:RR-1989)	15-11-1963
3	Shri V. Vinay Kumar (IPS:RR-1990)	21-10-1963

2- संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा उक्तानुसार प्रेषित नामों के पैनल में से सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा भारतीय पुलिस सेवा उत्तराखण्ड संवर्ग के आई.पी.एस. अधिकारी श्री अशोक कुमार, (IPS:RR-1989) को पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-17) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- सम्बन्धित अधिकारी उक्त पद का कार्यभार, वर्तमान पुलिस महानिदेशक, श्री अनिल कुमार रतूड़ी के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की तिथि दिनांक 30.11.2020(अपरान्ह) को ग्रहण करेंगे।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,  
सचिव।**श्रम अनुभाग****अधिसूचना**

25 नवम्बर, 2020 ई0

संख्या 1209/VIII-1/2020-06(श्रम)/2020-चूँकि, उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में संशोधन करने के लिए नियम का प्रारूप अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 817/VIII-1/2020-06(श्रम)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रकाशित किये गये थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उसमें प्रभावित होना संभाव्य है, से तीस दिनों की अवधि के अवसान होने से पहले, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गये थे ;



और चूँकि, अधिसूचना की प्रतियां दिनांक 30.08.2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और चूँकि, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव अब, राज्यपाल अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**उत्तराखण्ड [उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा - शर्त)]**

**(संशोधन) नियमावली, 2020**

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त)] (संशोधन) नियमावली, 2020 है।
- (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगी।
- (3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

- नियम 14 का संशोधन 2. उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

**स्तम्भ-1**

**विद्यमान नियम**

- (2) आवेदन प्रारूप 9 में तीन प्रतियों में होगा तथा लाइसेंस समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले दिया जायेगा और यदि आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो लाइसेंस को नवीनीकृत लाइसेंस जारी होने की ऐसी तिथि तक नवीनीकृत समझा जायेगा।

**स्तम्भ-2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

- (2) प्रत्येक-ठेकेदार श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल पर लाइसेंस अवधि, समाप्त होने की तिथि से कम से कम तीस दिन पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ नवीनीकरण आवेदन उपलब्ध ऑनलाइन प्रारूप में अपलोड करेगा और आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो लाइसेंस एक वर्ष के लिए नवीनीकृत समझा जायेगा।

आज्ञा से,

डा० हरबंस सिंह चुघ,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1209/VIII-1/2020-06(labour)/2020, Dehradun dated November 25, 2020 for general information.

### NOTIFICATION

November 25, 2020

**No. 1209/VIII-1/2020-06(labour)/2020--Where as,** the draft of rules to amend the UP Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1983 (as applicable in Uttarakhand) were published as required under sub-section(1) of section 35 of Inter-State Migrant Worker (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1979 vide notification no. 817/VIII-1/2020-06(Labour)/2020 dated 28.08.2020 of the Government of Uttarakhand inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected there by before the expiry of the period of thirty days ;

**And whereas,** copies of the said notification were made available to the public on the 30 August 2020;

**And whereas,** the objections and suggestions from public were not received in respect of the said drafts rules;

**Now, therefore** in exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 35 of Inter-State Migrant Worker (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1979 the Governor is pleased to allow to further amend the UP Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1983 (as applicable in Uttarakhand) in the context of Uttarakhand state.

**The Uttarakhand [UP Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service)] (Amendment) Rules, 2020.**

<b>Short title, extent and Commencement</b>	<p>1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand [UP Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service)] (Amendment) Rules, 2020.</p> <p>(2) It extends to whole of Uttarakhand.</p> <p>(3) It shall come into force at once.</p>
<b>Amendment of Rule 14</b>	<p>2. In the UP Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1983 (As applicable in Uttarakhand) for the existing sub-rule (2) of rule 14 as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-</p>

#### **Column-1**

##### **Existing Rules**

- (2) The application shall be in Form IX in triplicate and shall be made not less than thirty days before the date on which the license expires and if the application is so made the license shall be deemed to have been renewed until such date when the renewed license is issued.

#### **Column-2**

##### **Rules hereby substituted**

- (2) Every contractor shall upload the renewal application with proof of prescribed fee on official portal of the Labour Department, Uttarakhand Government on the available online format not less than thirty days before the date on which the license expires and if the application is so made the license shall be deemed to have been renewed for the next one year

By Order,

**Dr. HARBANS SINGH CHUGH,**  
Secretary.

**न्याय अनुभाग-3****अधिसूचना****नियुक्ति**

04 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 255/XXXVI-A-3/2020-208/01-T.C.-I-कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम-1984 (अधिनियम संख्या-66 सन् 1984) की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से, श्री सुजीत कुमार निबन्धक (प्रोटोकॉल), मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,  
प्रेम सिंह खिमाल,  
सचिव।

**सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1****प्रोन्नति/विज्ञप्ति**

01 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 1354/XXXI(1)/2020/पदो0-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती पदवन्ती धर्मशक्तू को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान लेवल-11 (वेतनमान रू0 67,700/-2,08,700) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती पदवन्ती धर्मशक्तू, अनु सचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3-उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70/डी0बी0/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं ज्येष्ठता के सम्बन्ध में विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4-अनु सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 1355/XXXI(I)/2020/पदो0-03/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री दिशान्त को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान रू0 56,100-रू0 1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दिशान्त, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3-उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70/डी0बी0/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4-श्री दिशान्त, अनुभाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,  
सचिव (प्रभारी)।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जनवरी, 2021 ई0 (पौष 12, 1942 शक सम्वत्)

### भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

### उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

#### अधिसूचना

26 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 F-9(29)(I)/RG/UERC/2020/923.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियां और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियां का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2018 (मुख्य विनियम) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :-

#### 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 होगा।
- (2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

#### 2 मुख्य विनियम के विनियम 33 (2) में संशोधन:

मुख्य विनियम के विनियम 33 के उप-विनियम 2(a)(v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा: अर्थात्:-

## “(2) वितरण

- (a) वितरण अनुज्ञापी को वित्तीय वर्ष हेतु कार्यशील पूँजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज अनुज्ञात होगा, जिसे निम्नानुसार संगणित किया जायेगा:
- (i) एक माह के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय;
  - (ii) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय का 15% की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स, धन
  - (iii) प्रचलित शुल्कों पर विद्युत के विक्रय से अपेक्षित राजस्व के दो माह के बराबर;
  - (iv) आयोग द्वारा अनुज्ञात वर्तमान देयों के संग्रहण में ऐसी कमी के वित्त पोषण हेतु आवश्यक पूँजी; ऋण
  - (v) वार्षिक विद्युत क्रय योजना के आधार पर विद्युत क्रय की लागत के एक माह के बराबर

## 3 मुख्य विनियम के विनियम 12 (6) में संशोधन:

मुख्य विनियम के विनियम 12(6) के उप-विनियम (k) एवं (l) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा: अर्थात्:-

“6” आवेदक के निष्पादन में कुछ उदाहरण-स्वरूप परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन, जिन्हें आयोग द्वारा नियंत्रणीय कारकों पर आरोपित किया जा सकता है, में निम्नलिखित सम्मिलित होगा किन्तु उन तक सीमित नहीं होगा:

- (a) भू अधिग्रहण मुद्दों के कारण समय और/या लागत बढ़ने के फलस्वरूप पूँजीगत व्यय में परिवर्तन,
- (b) एक परियोजना को लागू करने में दक्षता जिसके लिये ऐसी परियोजना की परिधि में अनुमोदित परिवर्तन, कानूनी लेवीज़ में परिवर्तन या अपरिहार्य घटनाओं और उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेंसी के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब को आरोपित नहीं किया जा सकता।
- (c) तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में परिवर्तन,
- (d) अशोध्य ऋण,
- (e) निष्पादन मानदंडों में परिवर्तन,
- (f) कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं में परिवर्तन,
- (g) समय-समय पर संशोधित उविनिआ (निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 के विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफलता, सिवाय उसके जहां ऐसे विनियमों के अनुसार छूट प्राप्त हो,
- (h) पूँजीगत व्ययों में परिवर्तन के कारण वित्त पोषण पद्धति में परिवर्तन,
- (i) आपूर्ति की गुणवत्ता में परिवर्तन,
- (j) प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों में परिवर्तन,
- (k) विद्युत खरीद देयता के निर्वहन पर अर्जित छूट;
- (l) बिजली खरीद देयता के विलंबित निर्वहन के कारण देर से भुगतान अधिभार;

## 4 मुख्य विनियम के विनियम 84 (3) में संशोधन:

मुख्य विनियम के विनियम 84(3) के द्वितीय नियम के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा: अर्थात्:-

“(1) उपरोक्त घटकों को निम्नांकित विनिर्दिष्ट तरीके से संगणित किया जायेगा :

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (1+CPI \text{ इन्फ्लेशन})$$

$$R\&M_n = K \times (GFA_{n-1}) \times (1+WPI \text{ इन्फ्लेशन}) \text{ और}$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (1+WPI \text{ इन्फ्लेशन}) + \text{प्रावधान}$$

जहां-

- $EMP_{n-1}$  = (n-1) वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- $A\&G_{n-1}$  = (n-1) वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

प्रावधान: वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा प्रमाणीकृत पहलों या अन्य एकबारी व्ययों के लिये लागत।

- 'K' % में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य, अनुज्ञापी की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्ययों के मुकाबले पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और कोई अन्य कारक जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जायें, पर आयोग के आदेश द्वारा अवधारित MYT शुल्क आदेश के आधार पर किया जायेगा;
- CPI इन्फ्लेशन- ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है;
- WPI इन्फ्लेशन- ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में औसत वृद्धि है;
- $GFA_{n-1}$  - n वें वर्ष के लिये वितरण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति;
- $G_n$  n वें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है और यह वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या उससे कम हो सकता है।  $G_n$  का मूल्य अनुज्ञापी की फाईलिंग, बेंचमार्किंग, और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, पर आधारित अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा;

परन्तु अवधारित मरम्मत और रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिये किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त आई0टी0 सम्बन्धित परिसंपत्तियों और गैर-आई0टी0 सम्बन्धित परिसंपत्तियों के लिए मरम्मत और रखरखाव के खर्च को इन विनियमों के अन्तर्गत अलग से गणना की जाएगी, यदि वितरण उपयोगिता (कम्पनी) इन विनियमों के तहत दावा किए गए आर एण्ड एम व्ययों की परिसंपत्तियों वार विवरण को अलग से अभिलेखित रखते हैं।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 01/प्रशा0/6(4)/उविनिआ/2020-21/971-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

	1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
	2. सदस्य (विधि), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	3. सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	4. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
	5. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
वाणिज्य एवं उद्योग	6. अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
	7. अध्यक्ष, सीआईआई, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
	8. अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाऊस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड़, काशीपुर	सदस्य
	9. प्रेसीडेंट, उत्तराखण्ड होटल एसोसियेशन, देहरादून	सदस्य
कृषि	10. संयुक्त निदेशक (नियोजन), कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।	सदस्य
जन परिवहन	11. उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।	सदस्य
	12. चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, उत्तर रेलवे, बडौदा हाऊस, नई दिल्ली।	सदस्य
शैक्षणिक एवं अनुसंधान	13. विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।	सदस्य
	14. अस्सिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
उपभोक्ता प्रतिनिधि	15. श्री एस0पी0सिंह राघव, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, 303, नर्मदा ब्लॉक, सिद्धार्थ पेराडाईज, पंडितवाड़ी, देहरादून।	सदस्य
	16. श्री राजीव कुमार अग्रवाल, 32, इन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून।	सदस्य
गैर सरकारी संगठन	17. श्री प्रकाश रावत, जय नन्दा वैलफेयर सोसाईटी (NGO) फ्लेट न0-06, लेन नं0-9, देवऋषि एनक्लेव, देहरादून।	सदस्य



विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सलाह देना है:-

- (i) major questions of policy;
- (ii) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
- (iii) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;
- (iv) protection of consumers interest; and
- (v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व सम्पन्न न कर दी जाय।

आयोग की आज्ञा से,  
नीरज सती,  
सचिव।

### कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि-अनुभाग)

16 दिसम्बर, 2020 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4089/आयु0 रा0कर, उत्तरा0/विधि-अनुभाग/Noti. Vol. I/2020-21/देहरादून-उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 943/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-81; 944/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-82; 945/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-84; 946/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-85 एवं 947/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-88 समदिनांकित 11 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 8 पर उल्लिखित उपबंध प्रवृत्त होने; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 2020 जारी किए जाने; धारा 39(1) के अन्तर्गत व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित किए जाने; तिमाही के प्रथम दो मासों के लिए कर दायित्व के 35 प्रतिशत का भुगतान किए जाने हेतु विशेष प्रक्रिया अधिसूचित किए जाने तथा अधिसूचना संख्या 330 दिनांक 20 मई, 2020 में अग्रेतर संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**वित्त अनुभाग-8****अधिसूचना**

11 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 943/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-81—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 13) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 नवंबर 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 8 पर उल्लिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 943/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-81, dated December 11, 2020 for general information.

**NOTIFICATION**

December 11, 2020

No. 943/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-81—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (13 of 2019) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor is pleased to allow to appoint the 10<sup>th</sup> day of November, 2020, as the date on which the provisions mentioned at Section 8 of the said Act, shall come into force.

**अधिसूचना**

11 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 944/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-82—राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्—

**उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तेरहवा संशोधन) नियम, 2020**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम<br>और प्रारंभ | 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तेरहवा संशोधन) नियम, 2020 है।<br>(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये दिनांक 10 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त समझे जायेंगे। |
|-----------------------------|---|

नियम 59 का  
संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम 2017 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 59 के स्थान पर 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी निम्नलिखित नियम, को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

## "59. जावक पूर्ति के ब्यौरे देने का प्ररूप और रीति -

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 की 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, धारा 37 के अधीन माल या सेवा या दानों के जावक पूर्ति के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित है, किसी मास के या तिमाही के लिए, जैसा भी मामला हो, प्ररूप जीएसटीआर -1 में ऐसे ब्यौरे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में, या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके द्वारा धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रदान किए गए माल या सेवा या दानों के ऐसे जावक पूर्ति के ब्यौरे, जैसा वह आवश्यक समझे, तिमाही के पहले या दूसरे माह में, प्रत्येक माह में पचास लाख रुपये का संचयी मूल्य तक, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, (जिसे उक्त अधिसूचना में "आई एफ एफ" कहा गया है) नियम 26 के अधीन विहित रिति में सम्यक रूप से अधिप्रमाणित, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से उस मास के 13वें दिन तक, प्रस्तुत कर सकता है।

(3) तिमाही के पहले और दूसरे माह में आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक पूर्ति के ब्यौरे को उक्त तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर - 1 में प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) प्ररूप जीएसटीआर - 1 में प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दानों के जावक पूर्ति के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) सभी के बीजकवार ब्यौरे -

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिक पूर्ति और

(ii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक बीजक मूल्य के साथ अन्तरराज्यिक पूर्ति

(ख) सभी के समेकित ब्यौरे -

(i) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया अन्तरराज्यिक पूर्ति और

(ii) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया दो लाख पचास हजार रुपये तक बीजक मूल्य के साथ राज्यवार अन्तरराज्यिक प्रदाय

(ग) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किया गए विकलन या प्रत्यय पत्र, यदि कोई हो।

(5) आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दोनों के जावक पूर्ति के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होगा -

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिक पूर्ति के बीजकवार ब्यौरे

(ख) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किए गए विकलन और प्रत्यय पत्र, यदि कोई हो।"

नियम 60 का  
संशोधन

3. मूल नियम में नियम 60 के स्थान पर 1 जनवरी 2021 से प्रभावी निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"60. जावक पूर्ति के अभिनिश्चित ब्यौरे का प्ररूप और रीति -

(1) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर - 1 में या आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक पूर्ति के ब्यौरे संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (प्राप्तिकर्ता) को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग क में, प्ररूप जीएसटीआर 4क में और प्ररूप जीएसटीआर 6क में, जैसा भी मामला हो, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) नियम 63 के अधीन किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-5 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग क में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) नियम 65 के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग ख में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) धारा 39 की उपधारा(3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-7 में कटौतिकर्ता द्वारा दिए गए स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-2 क के भाग ग में, जिससे कटौती की गयी है, को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) धारा 52 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-8 में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा दिए गए स्रोत पर एकत्र किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप माध्यम से संबंधित व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(6) प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लागू गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग घ में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर-2ख में स्वतः तैयार किया गया इनपुट कर प्रत्येक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :-

(i) पूर्ववर्ती माह की प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के ठीक पश्चात् दिन से चालू माह की प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच में उसके पूर्तिकार, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित पूर्तिकार से भिन्न है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक पूर्तियों के ब्यौरे,

(ii) प्ररूप जीएसटीआर-5 में अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटीआर-6 में इनपुट सेवा वितरक द्वारा अपनी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और उनके पूर्तिकार, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करते हैं, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर - 1 में या आई एफ एफ का प्रयोग करके प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो :-

(क) तिमाही के प्रथम मास के लिए, पूर्ववर्ती तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के प्रथम मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे प्रस्तुत करने की देय तारीख तक के बीच;

(ख) तिमाही के दूसरे मास के लिए, तिमाह के पहले मास के लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने के देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के दूसरे मास लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख तक बीच;

(ग) तिमाही के तीसरे मास के लिए, तिमाही के दूसरे मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर - 1 को देने की देय तारीख तक के बीच;

(iii) मास में प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र ईकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के ब्यौरे ।

(8) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2ख में विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे-

(i) तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आई एफ एफ में जावक पूर्तियों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् दिन, या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्तियों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् दिन, इसमें से जो भी पश्चातवर्ती हो;

(ii) तिमाही के तीसरे माह के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त माह की जावक पूर्तियों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करने की नियत तारीख के ठीक पश्चातवर्ती दिन से।

नियम 61 का संशोधन

4. मूल नियम के नियम 61 में उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(6) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, एकीकृत माल और सेवा अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति या इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर देने वाला कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के सिवाय उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से उत्तरवर्ती माह के 20वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेंगे।

परन्तु करदाता जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक का संकलित आवर्त है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह के लिए उक्त नियम के तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त माह के उत्तरवर्ती माह के 24वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

नियम 61 का संशोधन

5. मूल नियमों के नियम 61 के स्थान पर 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"61. विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति:-

(1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति या इनपुट सेवा प्रदाता या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 अथवा धारा 51 या यथासंघति धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से नीचे पथा विनिर्दिष्ट:-

(i) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसी अवधि के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा :

(ii) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिन को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शासति, फीस या इस अधिनियम अथवा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए इलेक्ट्रॉनिक नगद खाते या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के विकलन द्वारा उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा और विवरणी में ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सममिलित करेगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तिमाही के प्रत्येक पहले दो मास के उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन तक प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उक्त रकम के निक्षेप द्वारा धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के अधीन बकाया कर का संदाय करेगा:

परंतु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें अधिसूचित किए जाएं, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उक्त रकम का निक्षेप करने के लिए नियत तारीख का विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि, केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह और भी कि, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में निक्षेप करते समय ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति -

(क) तिमाही के पहले मास के लिए, इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा ;

(ख) तिमाही के दूसरे मास के लिए, पहले मास के लिए बकाया कर को अप्रवर्जित करते हुए इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा।

(4) उपरोक्त उपनियम (3) के परंतुक के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा निक्षिप्त रकम प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उक्त तिमाही के लिए विवरणी फाइल करते समय विकलित की जाएगी और इस प्रकार निक्षिप्त रकम में से इलैक्ट्रानिक नगद खाते में अतिशेष में पड़ी हुई ऐसी रकम के प्रतिदाय के किसी दावे को केवल उक्त तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-03ख में विवरणी फाइल किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा।"

नये नियम 61क 6. मूल नियमों के नियम 61 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"61क. तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए चयन की रीति.-

(1) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आशयित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पूर्ववर्ती तिमाही के दूसरे मास के पहले दिन से उस तिमाही के जिसके लिए चयन किया जाना है, उस तिमाही के पहले मास के अंतिम दिन तक इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उसकी प्राथमिकता उपदर्शित करेगा :

परंतु जहां एक बार ऐसे विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भविष्य कर अवधियों के लिए तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेगा, जब तक कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-

(क) इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपात्र नहीं हो जाता है; या

(ख) इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करता है;

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की तारीख पर बकाया अंतिम विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आवर्त पांच करोड़ रुपये से अधिक है, उस तिमाही जिसके दौरान उसका सकल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक होता है, वह उत्तरवर्ती तिमाही के पहले मास से इलैक्ट्रानिक रूप में सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करेगा।

नियम 62 का  
संशोधन

7. मूल नियमों के नियम 62 में,-

(i) उपनियम (1) में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों "या उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 281/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-2 दिनांक 09 अप्रैल, 2019 का लाभ प्राप्त किया है" का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4) में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों "या उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 281/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-2 दिनांक 09 अप्रैल, 2019 का लाभ प्राप्त किया है" का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपनियम (4) के स्पष्टीकरण में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों "या उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 281/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-2 दिनांक 09 अप्रैल, 2019 का लाभ प्राप्त किया है " का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

प्ररूप  
जीएसटीआर-1  
का संशोधन

8. प्ररूप जीएसटीआर-1 में, अनुदेश में, क्रमांक 17 के उपरान्त, निम्नलिखित अनुदेश डाला जाएगा, यानी:-

"18. धारा 46 के परंतुक के द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा माल या सेवाओं के लिए उल्लिखित एचएसएन कोड के अंकों की संख्या को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए निर्दिष्ट करना बाध्यकारी होगा।

नये प्ररूप 2ख  
का अन्तःस्थापन

9. प्ररूप -2क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-





[illegible]

[illegible]



II	बी२बी-डेविट नोट्स (संशोधन) आईएसडी से आवक प्रदाय	लागू नहीं						ऐसी क्रेडिट को जीएसटीआर-3ब में नहीं लिया जाएगा।
ब्योरा	आईएसडी- बीजक							
III	आईएसडी-संशोधन- बीजक रिवर्स चार्ज के लिए वायी (Libable) आवक प्रदाय	3.1 (घ)						कर भुगतान के लिए इन की आपूर्तियों की प्रमाण जीएसटीआर-3ब की सारणी 3.1 (घ) में की जाएगी। यद्यपि, उस पर क्रेडिट नहीं होगा।
ब्योरा	बी२बी- बीजक बी२बी-डेविट नोट्स बी२बी- बीजक (संशोधन) बी२बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
भाग ख	आईटीसी की वापसी							
I	अन्य	4 (ख) (2)						क्रेडिट को जीएसटीआर-3ब की सारणी 4 (ख) (2) के अंतर्गत वापस किया जाएगा।
ब्योरा	बी२बी-क्रेडिट नोट्स बी२बी-क्रेडिट नोट्स (संशोधन) बी२बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) बी२बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन) आईएसडी- क्रेडिट नोट्स आईएसडी- क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

## निर्देश:

1. प्रयुक्त शब्दावली-  
 क. आईटीसी - इनपुट टैक्स क्रेडिट  
 ख. बी2बी - बिजनेस टू बिजनेस  
 ग. आईएसडी - इनपुट्स सर्विस डिस्टीन्यूट  
 घ. आईएमपीजी - इम्पोर्ट ऑफ गुड्स  
 ङ. आईएमपीजीएसईजैड - इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोम एसईजैड

## 2. महत्वपूर्ण संलाह:

क) प्रारूप जीएसटीआर-2ब एक ऐसा विवरण है जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्रारूप जीएसटीआर-1, 5, और 6 में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। यह एक अचल विवरण है और एक माह में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्रारूप जीएसटीआर-1, 5 और 6 में से किसी में भी जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, उसे संबंधित आपूर्तिकर्ता के फाइलिंग की तारीख के अगले प्रारूप जीएसटीआर-2ब में दर्शाया जाएगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वो प्रारूप जीएसटीआर-2B का प्रयोग प्रारूप जीएसटीआर-3B में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिये करें। हालांकि, अतिरिक्त ब्यौरे की स्थिति में, वे संबंधित प्रारूप जीएसटीआर-2क (जिसे वास्तविक समय के आधार अद्यतन किया जाता रहता है) में और अधिक ब्यौरों के लिए देख सकते हैं।

ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट को निम्नलिखित स्थितियों में उपलब्ध न हुआ दर्शाया जाएगा:-

1. माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के उन बीजक या डेबिट नोट में, जहाँ उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का पात्र नहीं होता है।

2. उन बीजक या डेबिट नोट में, जहाँ आपूर्तिकर्ता (जीएसटीआईएन) और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में हो और प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में। हालांकि ऐसी अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जहाँ करदाता को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध न हो पाता हो और उसे सिस्टम द्वारा भी तैयार न किया गया हो। वहां करदाता को अपना आकलन स्वतः करना चाहिए और ऐसी क्रेडिट को प्रारूप जीएसटीआर-3ब में वापस कर देना चाहिए।

3. यह देखा जाना चाहिये कि प्रारूप जीएसटीआर-2ब में आपके संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये सभी जीएसटीआर-1s, 5s और 6s, हो सकते हैं, जो सामान्यतः संबंधित आपूर्तिकर्ता के द्वारा जुने गए विकल्प (मासिक या त्रैमासिक) के आधार पर दो लगातार जीएसटीआर-1 या आईएफएफ भरने की तारीख के बीच भरे गये हैं। जिस तारीख से संबंधित डाटा लिये गए हों उसे उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम में उल्लिखित है और ऑनलाइन पोर्टल पर "सलाह देखें" के अंतर्गत उपलब्ध करा दिया जाता है। उदाहरणार्थ फरवरी माह के जीएसटीआर-2ब में वे सभी दस्तावेज होंगे जो कि उन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये होंगे जिन्होंने अपने जीएसटीआर-1 को मासिक आधार पर भरने का विकल्प चुना होगा, जो कि 12 फरवरी के 00:00 बजे से लेकर 11 मार्च के 23:59 बजे तक का होगा।

4. इसमें आइसगेट सिस्टम से प्राप्त माल के आयात से संबंधित जानकारी भी शामिल होगी जिसमें विशेष आर्थिक जोन इकाईयों से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़े भी शामिल होंगे।

5. यह नोट किया जाना चाहिए कि सेवाओं के आयात पर लगने वाले प्रतिवर्ती प्रदाय कर का प्रत्यय का ब्यौरा इस विवरण में शामिल नहीं किया जाता है और इसे करदाताओं के द्वारा प्रारूप जीएसटीआर-3 ब के सारणी 4 (क) (2) में दर्शाया जाता रहेगा।

6. सारणी 3 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्रारूप जीएसटीआर-2ब में उत्पन्न करने की तारीख तक उपलब्ध होगा। इसे निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है।

क. भाग क में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्रारूप जीएसटीआर-3 ब की संबंधित सारणी में प्राप्त किया गया हो।

ख. भाग ख में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्रारूप जीएसटीआर-3 ब की संबंधित सारणी में वापस किया जाना है।

7. सारणी 4 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्रारूप जीएसटीआर-2ब में उत्पन्न करने की तारीख तक प्राप्त न किया गया हो। इस सारणी में उपलब्ध क्रेडिट को प्रारूप जीएसटीआर-3 ब में क्रेडिट के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा परंतु रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने का दायित्व और क्रेडिट नोट्स की प्राप्ति पर क्रेडिट को वापस करने का दायित्व ऐसे आपूर्तिकर्ताओं पर बना रहेगा।

8. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित रखें कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न किया गया डाटा उनके रिकॉर्ड और वही खाते से मेल खाता हो।

क. किसी भी परिस्थिति में किसी भी दस्तावेज पर क्रेडिट दोबारा न लें।

ख. जहाँ भी जरूरी हो वहाँ क्रेडिट को वापस कर दिया जाए।

ग. रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान अवश्य किया जाए।

9. बीजक, क्रेडिट नोट्स, डेविट नोट्स, आईएसडी बीजक, आईएसडी क्रेडिट और डेविट नोट्स, प्रविष्टि के बिल का ब्यौरा इत्यादि ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा और इसको डाउनलोड किये जाने की सुविधा भी होगी।

10. ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहाँ कर की लागू दर का प्रतिशत भी सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाए। जहाँ ऐसी दर लागू हो वहाँ बीजक/दस्तावेजों में एक अंक से कॉलम की व्यवस्था होगी।

11. सारणीवार निर्देश

सारणी सं. तथा शीर्षक	निर्देश
सारणी 3, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी - रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियाँ जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियाँ दर्शायी जाती हैं जिनपर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हों।</p> <p>iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, वीटबी, बीजक और डेविट नोट्स में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) (2) में वापस कर दिया जाएगा।</p>
सारणी 3, भाग क, खण्ड II आईएसडी से आवक प्रदाय	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर-6 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियाँ दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों।</p> <p>iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, आईएसडी संशोधन-बीजक में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) (2) में वापस कर दिया जाएगा।</p>
सारणी 3, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो	<p>i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियाँ आती हैं जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाता है, जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियाँ दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों।</p> <p>iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 (घ) में की जाएगी। कर के भुगतान पर क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (क) (3) के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है।</p>
सारणी 3, भाग क, खण्ड IV माल का आयात	<p>i. इस खण्ड में आपके द्वारा भुगतान किये गये उस आईटीसी का ब्यौरा होता है जो कि विदेश या एसईजैड इकाईयों/डेवलपर्स से किये गये माल के आयात पर बिल ऑफ एन्ट्री और उसके संशोधन में किया गया हो। इस ब्यारे को आईसगेट सिस्टम से निकटतम वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता रहता है।</p> <p>ii. इस सारणी में उन आयात से संबंधित डाटा होंगे जो कि आप (जीएसटीआईएन) के द्वारा उस महीने में किया गया हो जिस महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2ख को तैयार किया जा रहा हो।</p> <p>iii. आईसगेट की संदर्भ तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख से प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का पात्र बनता है।</p> <p>iv. इस सारणी में यह भी बताया गया है कि किन बिल ऑफ एन्ट्री में संशोधन हुआ है।</p> <p>v. यह जानकारी आईसगेट से प्राप्त डाटा के आधार पर सारणी में दी जाती है। कोरियर आयात जैसे कतिपय आयातों से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है।</p>

<p>सारणी 3, भाग ख, खण्ड I अन्य</p>	<p>i. इस खण्ड में प्राप्त क्रेडिट नोट्स और उसके संशोधन का ब्यौरा होता है जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई होती है और उसको उसने अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5 में किया होता है। ii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) (2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा। यदि यह मूल्य ऋणात्मक है तो क्रेडिट का पुनः दावा किया जा सकता बशर्ते कि उसको पहले किसी स्थिति में वापस कर दिया गया हो।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी-रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियां जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्तव्यों के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों। iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड II आईएसडी की आवक प्रदाय</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर-6 में दायर किया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों। iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होता है जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी होती हैं, जिनकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता के द्वारा की गई होती है और उसने उसे अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में दायर किया होता है। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों। iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 (घ) में की जाएगी। बहरहाल ऐसी आपूर्तियों पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगी।</p>
<p>सारणी 4, भाग ख, खण्ड I अन्य</p>	<p>i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियां आती हैं जिनपर क्रेडिट नोट की पावती एवं संशोधन हो और जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर-1 एवं 5 में दायर किया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों। iii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) (2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा।</p>



In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 944/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-82, dated December 11, 2020 for general information.

**NOTIFICATION**

*December 11, 2020*

**No. 944/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-82**--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendation of Council, is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:--

**The Uttarakhand Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2020**

**Short title and Commencement**

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall deemed to have been come into force on the 10<sup>th</sup> day of November, 2020.

**Amendment of Rule 59**

2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter referred to as the principal rules), for rule 59, the following rule shall be substituted with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2021 namely:-

**59. Form and manner of furnishing details of outward supplies:-**

(1) Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), required to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37, shall furnish such details in FORM GSTR-1 for the month or the quarter, as the case may be, electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre as may be notified by the Commissioner.

(2) The registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39 may furnish the details of such outward supplies of goods or services or both to a registered person, as he may consider necessary, for the first and second months of a quarter, up to a cumulative value of fifty lakh rupees in each of the months, - using invoice furnishing facility (hereafter in this notification referred to as the "IFF") electronically on the common portal, duly authenticated in the manner prescribed under rule 26, from the 1<sup>st</sup> day of the month succeeding such month till the 13<sup>th</sup> day of the said month.

(3) The details of outward supplies furnished using the IFF, for the first and second months of a quarter, shall not be furnished in FORM GSTR-1 for the said quarter.

(4) The details of outward supplies of goods or services or both furnished in FORM GSTR-1 shall include the--

(a) invoice wise details of all -

(i) inter-State and intra-State supplies made to the registered persons; and

(ii) inter-State supplies with invoice value more than two and a half lakhruppes made to the unregistered persons;

(b) consolidated details of all -

(i) intra-State supplies made to unregistered persons for each rate of tax; and

(ii) State wise inter-State supplies with invoice value upto two and a half lakh rupees made to unregistered persons for each rate of tax;

(c) debit and credit notes, if any, issued during the month for invoices issued previously.

(5) The details of outward supplies of goods or services or both furnished using the IFF shall include the --

(a) invoice wise details of inter-State and intra-State supplies made to the registered persons;

(b) debit and credit notes, if any, issued during the month for such invoices issued previously."

### Amendment of Rule 60

3. In the principal rules, for rule 60, the following rule shall be substituted with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2021, namely:-

"60. Form and manner of ascertaining details of inward supplies.-

(1) The details of outward supplies furnished by the supplier in FORM GSTR-1 or using the IFF shall be made available electronically to the concerned registered persons (recipients) in Part A of FORM GSTR-2A, in FORM GSTR-4A and in FORM GSTR-6A through the common portal, as the case may be.

(2) The details of invoices furnished by an non-resident taxable person in his return in FORM GSTR-5 under rule 63 shall be made available to the recipient of credit in Part A of FORM GSTR 2A electronically through the common portal.

(3) The details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in FORM GSTR-6 under rule 65 shall be made available to the recipient of credit in Part B of FORM GSTR 2A electronically through the common portal.

(4) The details of tax deducted at source furnished by the deductor under sub-section (3) of section 39 in FORM GSTR-7 shall be made available to the deductee in Part C of FORM GSTR-2A electronically through the common portal.

(5) The details of tax collected at source furnished by an e-commerce operator under section 52 in FORM GSTR-8 shall be made available to the concerned person in Part C of FORM GSTR 2A electronically through the common portal.

(6) The details of the integrated tax paid on the import of goods or goods brought in domestic Tariff Area from Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer on a bill of entry shall be made available in Part D of FORM GSTR-2A electronically through the common portal.

(7) An auto-drafted statement containing the details of input tax credit shall be made available to the registered person in

FORM GSTR-2B, for every month, electronically through the common portal, and shall consist of -

(i) the details of outward supplies furnished by his supplier, other than a supplier required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, in FORM GSTR-1, between the day immediately after the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the previous month to the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the month;

(ii) the details of invoices furnished by a non-resident taxable person in FORM GSTR-5 and details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in FORM GSTR-6 and details of outward supplies furnished by his supplier, required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, in FORM GSTR-1 or using the IFF, as the case may be,-

(a) for the first month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing of **FORM GSTR-1** for the preceding quarter to the due date of furnishing details using the IFF for the first month of the quarter;

(b) for the second month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing details using the IFF for the first month of the quarter to the due date of furnishing details using the IFF for the second month of the quarter;

(c) for the third month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing of details using the IFF for the second month of the quarter to the due date of furnishing of **FORM GSTR-1** for the quarter;

(iii) the details of the integrated tax paid on the import of goods or goods brought in the domestic Tariff Area from Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer on a bill of entry in the month.

(8) The Statement in **FORM GSTR-2B** for every month shall be made available to the registered person,-

(i) for the first and second month of a quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies for the said month, in the IFF by a registered person required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, or in **FORM GSTR-1** by a registered person, other than those required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, whichever is later;

(ii) in the third month of the quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies for the said month, in **FORM GSTR-1** by a registered person required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39."

#### Amendment of Rule 61

4. In the principal rules, in rule 61, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(6) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return in **FORM GSTR-3B**, electronically through

the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the twentieth day of the month succeeding such tax period:

Provided that for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such month."

**Amendment of  
Rule 61**

5. In the principal rules, for rule 61, the following rule shall be substituted with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2021, namely: -

**"61. Form and manner of furnishing of return:-**

(1) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return in FORM GSTR-3B, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, as specified under-

(i) sub-section (1) of section 39, for each month, or part thereof, on or before the twentieth day of the month succeeding such month;

(ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for each quarter, or part thereof, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such quarter.

(2) Every registered person required to furnish return, under sub-rule (1) shall, subject to the provisions of section 49, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger and include the details in the return in FORM GSTR-3B.

(3) Every registered person required to furnish return, every quarter, under clause (ii) of sub-rule (1) shall pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39, for each of the first two months of the quarter, by depositing the said amount in FORM GST PMT-06, by the twenty-fifth day of the month succeeding such month:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the due date for depositing the said amount in FORM GST PMT-06, for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner:

Provided also that while making a deposit in FORM GST PMT-06, such a registered person may —

- (a) for the first month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger.
- (b) for the second month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger excluding the tax due for the first month.

(4) The amount deposited by the registered persons under sub-rule (3) above, shall be debited while filing the return for the said quarter in FORM GSTR-3B, and any claim of refund of such amount lying in balance in the electronic cash ledger, if any, out of the amount so deposited shall be permitted only after the return in FORM GSTR-3B for the said quarter has been filed."

Insertion of new  
Rule 61A.

6. In the principal rules, after rule 61, the following rule shall be inserted, namely:-

**"61A. Manner of opting for furnishing quarterly return.-**

(1) Every registered person intending to furnish return on a quarterly basis under proviso to sub-section (1) of section 39, shall in accordance with the conditions and restrictions notified in this regard, indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis, electronically, on the common portal, from the 1<sup>st</sup> day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised:

Provided that where such option has been exercised once, the said registered person shall continue to furnish the return on a quarterly basis for future tax periods, unless the said registered person,—

- (a) becomes ineligible for furnishing the return on a quarterly basis as per the conditions and restrictions notified in this regard; or

(b) opts for furnishing of return on a monthly basis, electronically, on the common portal:

Provided further that a registered person shall not be eligible to opt for furnishing quarterly return in case the last return due on the date of exercising such option has not been furnished.

(2) A registered person, whose aggregate turnover exceeds 5 crore rupees during the current financial year, shall opt for furnishing of return on a monthly basis, electronically, on the common portal, from the first month of the quarter, succeeding the quarter during which his aggregate turnover exceeds 5 crore rupees.

**Amendment of  
Rule 62**

7. In the principal rules, in rule 62,

(i) in sub-rule (1), the words, figures, letters and brackets "or paying tax by availing the benefit of notification, of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 281/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-2, dated 09<sup>th</sup> April, 2019" shall be omitted;

(ii) in sub-rule (4), the words, figures, letters and brackets "or by availing the benefit of Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 281/2019/4(120)/ XXVII(8) /2019/CTR-2, dated 09<sup>th</sup> April, 2019" shall be omitted;

(iii) in the explanation to sub-rule (4), the words, figures, letters and brackets "or opting for paying tax by availing the benefit of notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 281/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-2, dated 09<sup>th</sup> April, 2019" shall be omitted;

(iv) sub-rule (6) shall be omitted.

**Amendment of  
FORM GSTR-1**

8. In FORM GSTR-1, in the Instructions, after serial number 17, the following instruction shall be inserted, namely:-

"18. It will be mandatory to specify the number of digits of HSN code for goods or services that a class of registered persons shall be required to mention as may be specified in the notification issued from time to time under proviso to rule 46 of the said rules.

**Insertion of new  
FORM-2B**

9. After FORM-2A, the following FORM shall be inserted, namely:-

**FORM-2B**

[See rule 60(7)]

Auto-drafted ITC Statement

(From FORM GSTR-1, GSTR-3, GSTR-6 and Import data received from ICEGATE)

Year	YYYY-YY
Month	

	DDMM/YYYY HH:MM

**3. ITC Available Summary**

(Amount in ₹ in all sections)

S.no.	Heading	GSTR-3B table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
Credit which may be availed under FORM GSTR-3B							
I	All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	4(A)(5)					If this is positive, credit may be availed under Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B. If this is negative, credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
Details	B2B - Invoices						
	B2B - Debit notes						
	B2B - Invoices (Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						
II	Inward Supplies from ISD	4(A)(4)					If this is positive, credit may be availed under Table 4(A)(4) of FORM GSTR-3B. If this is negative, credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
Details	ISD - Invoices						
	ISD - Invoices (Amendment)						





## 4. ITC Not Available Summary

(Amount in ₹ in all sections)						
S.no.	Heading	GSTR-3B Table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/L.T. Tax (₹)	Cess (₹)
Credit which may not be availed under FORM GSTR-3B						
I	All other ITC - Suppliers from registered persons other than reverse charge	NA				
Details	B2B - Invoices					Such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B
	B2B - Debit notes					
	B2B - Invoices (Amendment)					
	B2B - Debit notes (Amendment)					
II	Inward Supplies from ISD	NA				
Details	ISD - Invoices					Such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B
	ISD Amendment - Invoices					
III	Inward Supplies liable for reverse charge	3.1(d)				
Details	B2B - Invoices					These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax. However, credit will not be available on the same.
	B2B - Debit notes					
	B2B - Invoices (Amendment)					
	B2B - Debit notes (Amendment)					
I	Others	4(B)(2)				
Details	B2B - Credit notes					Credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
	B2B - Credit notes (Amendment)					



under the "View Advisory" tab on the online portal. For example, FORM GSTR-2B for the month of February will consist of all the documents filed by suppliers who choose to file their FORM GSTR-1 monthly from 00:00 hours on 12<sup>th</sup> February to 23:59 hours on 11<sup>th</sup> March.

4. It also contains information on imports of goods from the ICEGATE system including data on imports from Special Economic Zones Units / Developers.
5. It may be noted that reverse charge credit on import of services is not part of this statement and will be continued to be entered by taxpayers in Table 4(A)(2) of FORM GSTR-3B.
6. Table 3 captures the summary of ITC available as on the date of generation of FORM GSTR-2B. It is divided into following two parts:
  - A. Part A captures the summary of credit that may be availed in relevant tables of FORM GSTR-3B.
  - B. Part B captures the summary of credit that shall be reversed in relevant table of FORM GSTR-3B.
7. Table 4 captures the summary of ITC not available as on the date of generation of FORM GSTR-2B. Credit available in this table shall not be availed as credit in FORM GSTR-3B. However, the liability to pay tax on reverse charge basis and the liability to reverse credit on receipt of credit notes continues for such supplies.
8. Taxpayers are advised to ensure that the data generated in FORM GSTR-2B is reconciled with their own records and books of accounts. Tax payers shall ensure that
  - a. No credit shall be taken twice for any document under any circumstances.
  - b. Credit shall be reversed whenever necessary.
  - c. Tax on reverse charge basis shall be paid.
9. Details of invoices, credit notes, debit notes, ISD invoices, ISD credit and debit notes, bill of entries etc. will also be made available online and through download facility.
10. There may be scenarios where a percentage of the applicable rate of tax rate may be notified by the Government. A separate column will be provided for invoices / documents where such rate is applicable.
11. Table wise instructions:

Table No. and Heading	Instructions
Table 3 Part A Section I All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	<p>i. This section consists of the details of supplies (other than those on which tax is to be paid on reverse charge basis) which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5.</p> <p>ii. This table displays only the supplies on which input tax credit is available.</p> <p>iii. Negative credit, if any may arise due to amendment in B2B - Invoices and B2B - Debit notes. Such credit shall be reversed in Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.</p>

Table 3 Part A Section II Inward Supplies from ISD	<p>i. This section consists of the details of supplies, which have been declared and filed by an input service distributor in their FORM GSTR-6.</p> <p>ii. This table displays only the supplies on which ITC is available.</p> <p>iii. Negative credit, if any, may arise due to amendment in ISD Amendments - Invoices. Such credit shall be reversed in table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.</p>
Table 3 Part A Section III Inward Supplies liable for reverse charge	<p>i. This section consists of the details of supplies on which tax is to be paid on reverse charge basis, which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1.</p> <p>ii. This table provides only the supplies on which ITC is available.</p> <p>iii. These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax. Credit may be availed under Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B on payment of tax.</p>
Table 3 Part A Section IV Import of Goods	<p>i. This section provides the details of IGST paid by you on import of goods from overseas and SEZ units / developers on bill of entry and amendment thereof. These details are updated on near real time basis from the ICEGATE system.</p> <p>ii. This table shall consist of data on the imports made by you (GSTIN) in the month for which FORM GSTR-2B is being generated for.</p> <p>iii. The ICEGATE reference date is the date from which the recipient is eligible to take input tax credit.</p> <p>iv. The table also provides if the Bill of entry was amended.</p> <p>v. Information is provided in the tables based on data received from ICEGATE. Information on certain imports such as courier imports may not be available.</p>
Table 3 Part B Section I Others	<p>i. This section consists of the details of credit notes received and amendment thereof which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5</p> <p>ii. Such credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B. If this value is negative, then credit may be reclaimed subject to reversal of the same on an earlier instance.</p>
Table 4 Part A Section I All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	<p>i. This section consists of the details of supplies (other than those on which tax is to be paid on reverse charge basis), which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5.</p> <p>ii. This table provides only the supplies on which ITC is not available.</p> <p>iii. This is for information only and such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B.</p>
Table 4 Part A Section II	<p>i. This section consists of the details supplies, which have been declared and filed by an input service distributor in their FORM GSTR-6--</p>

Inward Supplies from ISD	<p>ii. This table provides only the supplies on which ITC is not available.</p> <p>iii. This is for information only and such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B.</p>
Table 4 Part A Section III Inward Supplies liable for reverse charge	<p>i. This section consists of the details of supplies liable for reverse charge, which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1.</p> <p>ii. This table provides only the supplies on which ITC is not available.</p> <p>iii. These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax. However, credit will not be available on such supplies.</p>
Table 4 Part B Section I Others	<p>i. This section consists details the credit notes received and amendment thereof which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5</p> <p>ii. This table provides only the credit notes on which ITC is not available.</p> <p>iii. Such credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.</p>

**अधिसूचना**

11 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 945/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-84—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जो कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न हैं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक का कुल आवर्त है और जिन्होंने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 61क के उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक त्रैमास के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जनवरी, 2021 से प्रत्येक त्रैमास के लिए विवरणी दाखिल करेंगे और मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के अनुसार प्रत्येक मास में शोध कर का संदाय करेंगे, अर्थात्:-

(i) ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को पूर्ववर्ती मास के लिए शोध विवरणी दाखिल की जा चुकी है;

(ii) जहां ऐसे विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया है, वहां वे भविष्यवर्ती कर अवधियों के लिए चयनित विकल्प के अनुसार विवरणी दाखिल करते रहेंगे, यदि वे उसका पुनरीक्षण नहीं करते।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका कुल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में त्रैमास के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, तो वह उत्तरवर्ती त्रैमास के पहले मास से त्रैमासिक आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसने अक्टूबर, 2020 की कर अवधि के लिए विवरणी 30 नवम्बर, 2020 को या उसके पूर्व दाखिल कर दी है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने मूल नियम के नियम 61क के उपनियम (1) के तहत उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाउल्लिखित विवरणी के मासिक या त्रैमासिक आधार पर दाखिल करने का विकल्प चुना है:-

**सारणी**

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	समझा गया विकल्प
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक आधार पर प्ररूप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है।	त्रैमासिक विवरणी

2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में मासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है।	मासिक विवरणी
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक है।	त्रैमासिक विवरणी

(4) ऊपर सारणी के स्तंभ (2) के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 5 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक अवधि के दौरान सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिफॉल्ट विकल्प बदल सकते हैं।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 945/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-84, dated December 11, 2020 for general information.

#### NOTIFICATION

December 11, 2020

**No. 945/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-84**—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 39 read with proviso to sub-section (7) of section 39 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the principal Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the registered persons, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the preceding financial year, and who have opted to furnish a return for every quarter, under sub-rule (1) of rule 61A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the principal rules) as the class of persons who shall, subject to the following conditions and restrictions, furnish a return for every quarter from January, 2021 onwards, and pay the tax due every month in accordance with the proviso to sub-section (7) of section 39 of the principal Act, namely: —

(i) the return for the preceding month, as due on the date of exercising such option, has been furnished;

(ii) where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods, unless they revise the same.

(2) A registered person whose aggregate turnover crosses five crore rupees during a quarter in a financial year shall not be eligible for furnishing of return on quarterly basis from the first month of the succeeding quarter.

(3) For the registered person falling in the class specified in column (2) of the Table below, who have furnished the return for the tax period October, 2020 on or before 30<sup>th</sup> November, 2020, it shall be deemed that they have opted under sub-rule (1) of rule 61A of the principal rules for the monthly or quarterly furnishing of return as mentioned in column (3) of the said Table:-



Table

Sl. No.	Class of registered person	Deemed Option
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR-1 on quarterly basis in the current financial year	Quarterly return
2.	Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR-1 on monthly basis in the current financial year	Monthly return
3.	Registered persons having aggregate turnover more than 1.5 crore rupees and up to 5 crore rupees in the preceding financial year	Quarterly return

(4) The registered persons referred to in column (2) of the said Table, may change the default option electronically, on the common portal, during the period from the 5th day of December, 2020 to the 31st day of January, 2021.

### अधिसूचना

11 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 946/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-85—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिन्होंने प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, जो तिमाही के पहले मास या दूसरे मास या दोनों मास में उस विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेंगे कि उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के समानुपाती रकम का इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में जमा करके मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन शोध्य कर का संदाय कर सकेंगे, -

(i) जहां विवरणी त्रैमासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां पूर्ववर्ती त्रैमास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व का पैटीस प्रतिशत या

(ii) जहां विवरणी मासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां ठीक पूर्ववर्ती त्रैमास के अंतिम मास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व:

परन्तु जहां -

(क) त्रैमास के पहले मास के लिए, जहां उक्त मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है;

(ख) त्रैमास के दूसरे मास के लिए जहां त्रैमास के पहले और दूसरे मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, संचयी कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है,

वहां ऐसी कोई रकम जमा करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त विशेष प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने पूर्ववर्ती ऐसे मास की पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं की है।

स्पष्टीकरण. - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पूर्ण कर अवधि" पद से वह कर अवधि अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक रजिस्ट्रीकृत होता है।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 946/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-85**, dated December 11, 2020 for general information.

#### NOTIFICATION

*December 11, 2020*

**No. 946/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-85**--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 read with sub-section (7) of section 39 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), (hereinafter referred to as the principal Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the registered persons, notified under proviso to sub-section (1) of section 39 of the principal Act, who have opted to furnish a return for every quarter or part thereof, as the class of persons who may, in first month or second month or both months of the quarter, follow the special procedure such that the said persons may pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39 of the principal Act, by way of making a deposit of an amount in the electronic cash ledger equivalent to, -

(i) thirty five per cent. of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly; or

(ii) the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return is furnished monthly:

Provided that no such amount may be required to be deposited-

- (a) for the first month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where there is nil tax liability ;
- (b) for the second month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first and the second month of the quarter or where there is nil tax liability:

Provided further that registered person shall not be eligible for the said special procedure unless he has furnished the return for a complete tax period preceding such month.

*Explanation-* For the purpose of this notification, the expression "a complete tax period" means a tax period in which the person is registered from the first day of the tax period till the last day of the tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2021.

### अधिसूचना

11 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 947/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-88—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 330/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-13 दिनांक 20 मई, 2020 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में, प्रथम प्रस्तर में, '01 जनवरी 2021 से प्रभावी, शब्द "पांच सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

आज्ञा से,

सौजन्या,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 947/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-88**, dated December 11, 2020 for general information.

**NOTIFICATION**

December 11, 2020

**No. 947/2020/7(120)/XXVII(8)/2020/CT-88**--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, No. 330/2020/5(120)/XXVII (8)/2020/CT-13, dated 20<sup>th</sup> May, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2021, for the words "five hundred crore rupees", the words "one hundred crore rupees" shall be substituted.

By Order,

SOWJANYA,  
Secretary.

अनिल सिंह,  
अपर आयुक्त राज्य कर,  
मुख्यालय, देहरादून।